Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

मान का केंद्र पर हमला, विदेश नीति पर सवाल

8 मई 2026: बपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 19 मई 2026 को संगरूर में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश और आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार खाड़ी युद्ध की स्थिति का इस्तेमाल अपनी नीतिगत विफलताओं को छुपाने के लिए कर रही है और देश में अघोषित लॉकडाउन जैसा माहौल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश वैश्विक संकट से प्रभावित हैं, लेकिन भारत के अलावा किसी अन्य देश ने अपने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल, गैस या सोने की खरीद को लेकर इस तरह की अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों में डर फैलाने के बजाय तेल, एलपीजी और सोने के भंडारों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मान ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कभी भारत को "विश्व गुरु" बनाने का दावा करने वाली सरकार ने अब देश को "विश्व चेला" बना दिया है।

सतौज से शुरू हुआ पंजाब का 'खंभा-मुक्त' अभियान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 19 मई 2026 को अपने पैतृक गांव सतौज से बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांव में 41 किलोमीटर बिजली केबल जमीन के अंदर बिछाई जाएगी और 384 बिजली खंभे हटाए जाएंगे। करीब 8 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में बिना सड़क खोदे ट्रेंचलेस तकनीक से केबल डाली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे फसलों में आग लगने, करंट हादसों और तूफान के दौरान बिजली कटौती जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब देश का पहला "खंभा-मुक्त गांवों" वाला राज्य बनेगा और "सतौज मॉडल" पूरे देश के लिए उदाहरण साबित होगा।और किसानों को सुरक्षित व निर्बाध बिजली मिलेगी। इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

चंडीगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की शानदार बैठक

18 मई 2026 : चंडीगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन (सीपीए) की जनरल हाउस मीटिंग 18 मई 2026 को सेक्टर-18 स्थित लायंस क्लब, चंडीगढ़ में भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। कार्यक्रम में लगभग 200 सदस्यों, वरिष्ठ फोटोग्राफर्स और विशेष अतिथियों ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल एसोसिएशन की उपलब्धियों का उत्सव बना, बल्कि फोटोग्राफी जगत के अनुभवी कलाकारों को सम्मान देने का भी महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ फोटोग्राफर्स को मंच पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मान दिया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। इनमें सुरेश शर्मा (इंडियानो स्टूडियो) विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल है। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और गरिमामय बना दिया।

एसोसिएशन के महासचिव सुनील भट्ट ने अध्यक्ष सरोज सिंह चौहान और संस्थापक सदस्य व कोषाध्यक्ष सुभाष भाटिया के नेतृत्व में पिछले नौ महीनों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्यों ने पूरी मेहनत, समर्पण और निष्ठा के साथ संगठन के हित में कार्य किया है।

मीटिंग में एसोसिएशन की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। इनमें सीपीए की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लगभग पूर्ण रूप से अपडेट करना सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो पिछले करीब दो दशकों से लंबित थी। इसके अलावा बैंक खाते की व्यवस्थाओं को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया गया तथा सीधे भुगतान के लिए स्कैनर सुविधा शुरू की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से सदस्यों के लिए जीरो बैलेंस खाते खोलने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई।

एसोसिएशन ने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। पिछले वर्ष पंजाब बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग प्रदान किया गया, जबकि साहिबजादों के शहीदी सप्ताह के दौरान लंगर सेवा का आयोजन भी किया गया। साथ ही आने वाले महीनों में राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना की घोषणा की गई।

कार्यक्रम की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि अध्यक्ष सरोज सिंह चौहान को पंजाब की एक फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन में संयुक्त सचिव नियुक्त किया जाना रहा। इसे चंडीगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की बढ़ती लोकप्रियता और सक्रिय कार्यशैली का बड़ा सम्मान माना जा रहा है। सदस्यों ने विश्वास जताया कि इससे पूरे पंजाब में सीपीए की पहचान और मजबूत होगी तथा फोटोग्राफर्स समुदाय को नए अवसर मिलेंगे।

'रंगला पंजाब' प्रोजेक्टों में तेजी लाने के आदेश

19 मई 2026: पंजाब सरकार ने 'रंगला पंजाब विकास स्कीम' के तहत चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्त रुख अपनाया है। 19 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने पहले चरण के विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले चरण से संबंधित सभी सत्यापित बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) तुरंत निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जाएं ताकि परियोजनाओं की वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवाड़ भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 'रंगला

पंजाब विकास स्कीम' के दूसरे चरण की रणनीति तय करना और उसकी समयबद्ध शुरुआत सुनिश्चित करना था। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के सभी विकास कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू और पूरे किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

जवाबदेही तय करने के लिए वित्त मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को मई महीने के अंत तक दो विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के आदेश दिए। पहली रिपोर्ट में उन कारणों का उल्लेख करना होगा जिनकी वजह से पहले चरण के कार्य 31 मई तक पूरे नहीं हो सके। दूसरी रिपोर्ट में दूसरे चरण के विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना, समय सीमा और क्रियान्वयन रणनीति का खाका पेश करना होगा।

बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों को हर सप्ताह परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करने के आदेश दिए, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की गति बनी रहे और किसी भी बाधा को समय रहते दूर किया जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में पंजाब के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा संबंधित प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि 'रंगला पंजाब विकास स्कीम' राज्य के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी परिवारों की ढाल

19 मई 2026: बीमारी का दर्द अक्सर आर्थिक संकट भी साथ लेकर आता है। अस्पताल का खर्च कई परिवारों को कर्ज, गहने गिरवी रखने और बचत खत्म होने की स्थिति में पहुंचा देता है। 2021 की एक स्वास्थ्य अध्ययन रिपोर्ट में भी सामने आया था कि भारत में इलाज का भारी खर्च परिवारों को गरीबी की ओर धकेल देता है, खासकर कैंसर और दिल की बीमारियों के मामलों में।

इसी बीच पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है। 16 मई 2026 तक इस योजना के तहत 1.59 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है और 3.11 लाख से ज्यादा मेडिकल प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। सरकार द्वारा अब तक ₹522 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई है।

पंजाब सरकार की यह योजना हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराती है।

'गैंगस्टरों ते वार' में 218 गिरफ्तार, छापेमारी तेज

8 मई 2026 : पंजाब में गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। 19 मई 2026 को 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 119वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में गैंगस्टरों के साथियों के 512 चिन्हित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 13 हथियारों सहित 218 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 30,475 तक पहुंच गई है।

यह अभियान 20 जनवरी 2026 को डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और जिला पुलिस टीमें मिलकर पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं। कार्रवाई के दौरान 133 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कदम उठाए गए, जबकि पूछताछ के बाद 17 लोगों को रिहा किया गया। पुलिस ने पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से अपराधियों और गैंगस्टरों की जानकारी साझा करें।

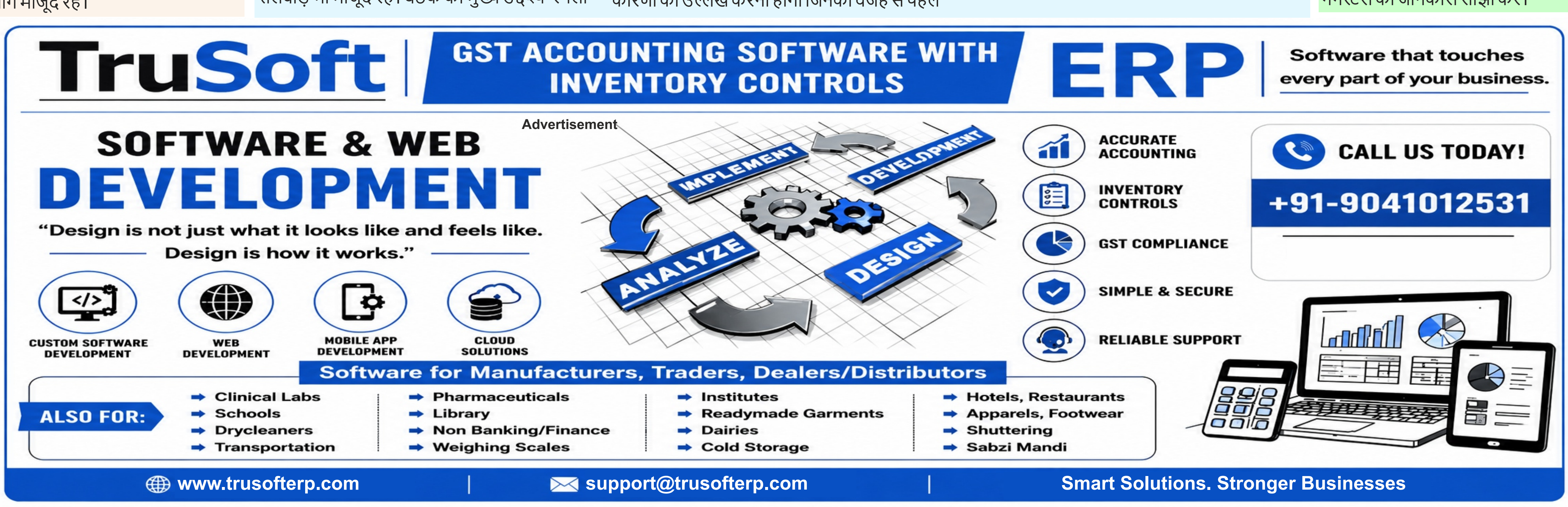

जनगणना फॉर्म में आपत्तिजनक शब्दों पर उठी आवाज

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जनगणना 2027 के लिए तैयार किए गए फॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अनुसूचित जातियों के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए प्रतिबंधित और अपमानजनक शब्दों का गंभीर नोटिस लिया है। इसी मुद्दे को लेकर 19 मई 2026 को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की और इस संबंध में एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा।

चंडीगढ़ में जारी जानकारी के अनुसार, आयोग ने मांग की है कि जनगणना 2027 से जुड़े सभी फॉर्मेट, सूचियों और स्व-गणना डिजिटल पोर्टलों से अनुसूचित जातियों के लिए इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक शब्दावली को तुरंत हटाया जाए। आयोग का कहना है कि इस प्रकार की भाषा न केवल सामाजिक रूप से अपमानजनक है, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई आयोग के पास दर्ज शिकायत नंबर 1211/26/पीएसएससीसी/5325-26 के आधार पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी दस्तावेजों और जनगणना से जुड़े प्लेटफॉर्मों पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें पहले ही प्रतिबंधित और अस्वीकार्य माना जा चुका है।

चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने मांग पत्र में कहा कि सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14, 17 और 21 का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 21 सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है।

गढ़ी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को तुरंत निर्देश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियां दोबारा न हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनगणना और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली भाषा की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हों।

आयोग का कहना है कि सरकारी दस्तावेज केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि वे समाज के प्रति सरकार की सोच और संवेदनशीलता को भी दर्शाते हैं। इसलिए उनमें सम्मानजनक और संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल बेहद जरूरी है।इस मुद्दे के सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों और दलित अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी आयोग की पहल का समर्थन किया है।

डिश टीवी का 'वीजेडवाई' बदलेगा मनोरंजन अनुभव

भारत में मनोरंजन देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब लोग लाइव टीवी, ओटीटी ऐप्स, स्मार्ट टीवी और मोबाइल स्क्रीन के बीच लगातार स्विच करते रहते हैं। अलग-अलग ऐप्स, कई सब्सक्रिप्शन, अलग बिल और बार-बार लॉग-इन की परेशानी ने मनोरंजन को आसान के बजाय जटिल बना दिया है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 18 मई 2026 को डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने

'वीजेडवाई एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम' लॉन्च किया, जिसे भारत का पहला ऐसा एकीकृत मनोरंजन प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है, जो लाइव टीवी, ओटीटी और प्रीमियम कंटेंट को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है।

डिश टीवी का कहना है कि आज का दर्शक सिर्फ नया ऐप नहीं चाहता, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जहाँ पूरा मनोरंजन बिना किसी परेशानी के आसानी से मिल सके। वीजेडवाई इसी सोच पर आधारित है। यह एक टू-लेयर एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है, जो अलग-अलग स्क्रीन और सेवाओं को जोड़कर एक सहज अनुभव प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य दर्शकों को बार-बार ऐप बदलने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट खोजने की परेशानी से मुक्त करना है।

वीजेडवाई प्लेटफॉर्म पर 29 से अधिक ओटीटी ऐप्स उपलब्ध हैं और भविष्य में इनमें और सेवाएँ जोड़ी जाएंगी। इसके साथ लाइव टीवी चैनल, क्रिएटर आधारित कंटेंट और विज्ञापन आधारित मुफ्त वीडियो यानी एवीओडी कंटेंट भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसकी स्मार्ट सर्च तकनीक उपयोगकर्ताओं को ट्रेंडिंग और पसंदीदा कंटेंट जल्दी खोजने में मदद करेगी। मोबाइल, स्मार्ट टीवी और टैबलेट जैसे अलग-अलग डिवाइस पर इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक साइन-इन और एक बिल के जरिए पूरा मनोरंजन उपलब्ध कराने का दावा किया गया है।

कंपनी ने वीजेडवाई स्मार्ट टीवी इकोसिस्टम भी पेश किया है। यह प्रीमियम क्यूएलईडी 4के स्मार्ट टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें डॉल्बी विजन व डॉल्बी एटमॉस जैसी आधुनिक तकनीक दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह टीवी घर बैठे सिनेमाघर जैसा अनुभव देगा।

लॉन्च के मौके पर डिश टीवी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज डोभाल ने कहा कि भारतीय दर्शक अब ऐसा मनोरंजन अनुभव चाहते हैं, जो बिना रुकावट के मोबाइल से लेकर लिविंग रूम के टीवी तक आसानी से काम करे। उन्होंने कहा कि वीजेडवाई सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि भारत में कंटेंट देखने के तरीके को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है।

डिश टीवी के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर सुखप्रीत सिंह ने कहा कि आज के दौर में दर्शक आसान, किफायती और व्यक्तिगत मनोरंजन अनुभव चाहते हैं। वीजेडवाई का लक्ष्य लोगों को कम समय में उनकी पसंद का कंटेंट उपलब्ध कराना और भारतीय परिवारों के लिए बेहतर तथा जुड़ा हुआ डिजिटल मनोरंजन अनुभव तैयार करना है।

अमृतसर में BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़, ग्रेनेड बरामद

पंजाब को सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के अभियान के तहत काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) समर्थित एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 18 मई 2026 को की गई कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजनाला के बाजीगर मोहल्ला निवासी अजय और अमृतसर के फत्तेवाल कलां निवासी जोधबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनकी काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

डीजीपी गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि बरामद ग्रेनेड सरकारी संस्थानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि विदेश में बैठे हैंडलरों ने अपने साथियों को ग्रेनेड उपलब्ध कराए हैं और उन्हें लोहारका रोड इलाके में एक अन्य सहयोगी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए थे।सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने नाका लगाकर दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पुलिस अब इस नेटवर्क के आगे और पीछे के लिंक खंगाल रही है ताकि अन्य सहयोगियों की पहचान की जा सके।इस मामले में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 4 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

विजिलेंस की कार्रवाई, 12 कर्मचारी गिरफ्तार

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने अप्रैल 2026 के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अलग-अलग ट्रैप मामलों में 12 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने अप्रैल महीने में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न अदालतों में 59 विजिलेंस मामलों के चालान पेश किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की गहराई से जांच के लिए 4 नई विजिलेंस जांचें भी दर्ज की गईं।

प्रवक्ता ने बताया कि बीते महीने कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 21 आरोपी नामजद किए गए हैं। इनमें 17 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने इन मामलों में रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 के दौरान ब्यूरो द्वारा अदालतों में लड़े गए चार रिश्वतखोरी मामलों में फैसला भी आया। इन मामलों में कुल 20 लोगों को दोषी करार देते हुए अदालतों ने दो साल से लेकर पांच साल तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर ₹10 हजार से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है।

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, विभाग अब डिजिटल निगरानी, शिकायत पोर्टल और गुप्त सूचना तंत्र को और मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की घटनाओं को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। आम लोगों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कई मामलों में कार्रवाई की गई, जिससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार ट्रैप कार्रवाई और त्वरित कानूनी प्रक्रिया से सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों में भी यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कानून से बचने का मौका नहीं मिलेगा।

वहीं, राज्य सरकार ने भी साफ किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उसकी प्राथमिकता है। सरकार का कहना है कि ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कदम जारी रहेंगे।

Advertisement

From Foundation to Finish – We Build Everything!

We specialize in high-quality construction services for: Residential Homes, Commercial Buildings Kothi & Luxury Villas, Showrooms & Shops, Flats & Apartments

WE PROMISE YOU FOR A BETTER FUTURE!

N M CONSTRUCTION
Excellence in every structure

#219 GF Maa Shimla Complex, Landran Road, Kharar, SAS Nagar, 140301, Punjab
Email: nmconstruction5151@gmail.com | Phone: +91-6009610096, 9872766841

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.